>

Title: Regarding implementation of Government schemes and programmes by Autonomous bodies - Laid

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा हमारे देश में जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है । लोकतंत्र, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके तहत जनता को अपनी मर्जी से अपना शासक चुनने का अधिकार प्राप्त होता है । जनता के माध्यम से चुने गये शासक द्वारा देश के सर्वागीण विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि सरकार द्वारा संचालित की जारी कल्याणकारी योजनाओं में देश के कुछेक स्वायत्त निकाय अनावश्यक रूप से अड़चन पैदा करते हैं, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है ।

देश की स्वायत्त संस्थाएं, जिन्हें अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा धन का आबंटन किया जाता है, उनका यह नैतिक कर्तव्य । बनता है कि वह सरकार द्वारा देश के विकास हेतु क्रियान्वित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से आगे बढ़ाने हेतु सरकार के साथ तत्परता के साथ सकारात्मक कार्यवाही करें, न कि बाधा उत्पन्न करें ।

इस संदर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए देश की ऐसी स्वायत्त संस्थायें, जो देश के विकास हेतु चलायी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बाधा या अड़चन पैदा करती हैं अथवा सरकार के सुझाव की अनदेखी करती है, उनके विरूद्ध जनहित में आवश्यक पहल करते हुए ऐसी व्यवस्था करें कि स्वायत्त संस्थायें देश की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में व्यवधान न उत्पन्न करें/सरकार के सुझाव की अनदेखी न करें ।